Regional Economic Cooperation: NAFTA, EU, ASEAN and SAARC

मयि श्री श्रयतां यशः 20

Unit: 3

Course Code: CMRC3036

Course Title: International Business

Programme: B.Com.(H)

Avneesh Kumar

Regional Economic Cooperation क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग

• Going beyond the theoretical reasons of international trade, **practical difficulties** poses challenge to international trade. There is **no parity** in the availability of **diverse resources** among countries. Over a period of time, some countries became more economically and technologically prosperous and progressed into **developed economies**, and most of the countries remained as **underdeveloped** or **developing economies**.

(अंतरराष्ट्रीय व्यापार के सैद्धांतिक कारणों से जब आगे बढ़ते हैं तब अंतरराष्ट्रीय व्यापार के व्यवहारिक समस्याओं से सामना होता है। देशों के बीच विविध संसाधनों की उपलब्धता में समता नहीं है। समयांतर में कुछ देश आर्थिक और तकनीकी रूप से ज्यादा समृद्ध होकर विकसित अर्थव्यवस्था में तब्दील हो गए और ज्यादातर देश अल्पविकसित या विकासशील अर्थव्यवस्था बनकर ही रह गए।)

• Regional economic cooperation has emerged as a result of underdeveloped and developing countries' inability to protect their economic interests while being isolated amidst increasing competition in global trade. Even developed economies formed their own regional groupings. Such economic groupings play prominent role during trade negotiations at WTO.

(वैश्विक व्यापार के बढ़ते प्रतिस्पर्धा के बीच अल्प विकसित तथा विकासशील देशों द्वारा अलग-थलग रहकर अपने आर्थिक हितों की रक्षा करने में अक्षमता का एहसास होने के परिणाम स्वरुप क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग का उद्भव हुआ। यहां तक कि विकसित अर्थव्यवस्थाओं ने भी अपने क्षेत्रीय आर्थिक समूहों का गठन किया।विश्व व्यापार संगठन में व्यापार वार्ता के दौरान ऐसे आर्थिक समूह प्रमुख भूमिका निभाते हैं।)

• NAFTA, EU, ASEAN and SAARC are groupings of countries for regional economic cooperation based on **geographical proximity**. BRICS is a grouping of countries for economic cooperation not based on geographical proximity rather is based on **socio-economic similarity**.

(भौगोलिक निकटता के आधार पर क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग के लिए नाफ्टा, यूरोपीय संघ, आसियान और सार्क देशों के समूह हैं। ब्रिक्स क्षेत्रीय आर्थिक, समहयोग के लिए देशों का एक समूह है जो भौगोलिक निकटता पर आधारित नहीं है बल्कि सामाजिक-आर्थिक समानता पर आधारित है।)

North American Free Trade Agreement (NAFTA) उत्तरी अमेरिका निर्वाध व्यापार समझौता (नाफ्टा)

- Establishment Date: January 1, 1994
- Type of Economic Grouping: Free trade area
- Member Nations: United States, Canada and Mexico
- Following intense negotiations and revised agreements among the member countries NAFTA has been superseded by United States—Mexico—Canada Agreement (USMCA) in March, 2020.

(सदस्य देशों के बीच गहन बातचीत और संशोधित समझौतों के बाद, NAFTA को मार्च, 2020 में संयुक्त राज्य-मेक्सिको-कनाडा समझौते (USMCA) द्वारा बदल दिया गया है।)

• USMCA is one of the largest regional economic groupings in the world by volume of trade (\$1.2 trillion approximately.)

(यूएसएमसीए व्यापार की मात्रा के हिसाब से (लगभग 1.2 ट्रिलियन डॉलर) दुनिया के सबसे बड़े क्षेत्रीय आर्थिक समूहों में से एक है।)

United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA) संयुक्त राज्य-मेक्सिको-कनाडा समझौता (यूएसएमसीए)

• SALIENT PROVISIONS(प्रमुख प्रावधान):

• Automobile (ऑटोमोबाइल)

• To qualify for zero tariffs, a car or truck must have 75 % of its components should be manufactured in Canada, Mexico or the United States. Besides that, cars and trucks must have at least 30 % of the work on the vehicle done by workers earning at least \$16 per hour.

शून्य टैरिफ के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए, कार या ट्रक का 75% हिस्सा कनाडा, मैक्सिको या संयुक्त राज्य अमेरिका में निर्मित होना चाहिए। इसके अलावा, कार और ट्रकों को कम से कम \$16 प्रति घंटे की दर से कमाई वाले श्रमिकों द्वारा वाहन पर कम से कम 30% काम करना चाहिए।

• Labour (श्रम)

• USMCA requires Mexico to change its laws to make it easier for workers to form labour unions.

यूएसएमसीए के अनुसार, मजदूरों के लिए आसानी से मजदूर संघ बनाने के लिए मेक्सिको अपने कानूनों में जरूरी बदलाव लाएगा।

United States—Mexico—Canada Agreement संयुक्त राज्य-मेक्सिको-कनाडा समझौता

• SALIENT PROVISIONS(प्रमुख प्रावधान):

• Dairy & Poultry (दूध और मुर्गी पालन)

• U.S. farmers will now be able to sell more "Class 7" dairy products like milk powder and ice cream to Canada. Besides that U.S. poultry firms can sell more eggs and turkeys to Canada. (अब अमेरिकी किसान दूध के पाउडर और आइसक्रीम जैसे "क्लास 7" डेयरी उत्पादों को कनाडा में अधिक बेच सकेंगे। इसके अलावा अमेरिकी पोल्ट्री फर्म कनाडा को अधिक अंडे और टर्की बेच सकते हैं।)

• Intellectual Property Rights (बौद्धिक संपदा अधिकार)

• More stringent protections have been provided for patents and trademarks, especially for biotech, financial services and domain names in USMCA.

यूएसएमसीए में पेटेंट और ट्रेडमार्क के लिए अधिक कठोर सुरक्षा प्रदान की गई है, विशेष रूप से बायोटेक, वित्तीय सेवाओं और डोमेन नामों के लिए।

United States-Mexico-Canada Agreement संयुक्त राज्य-मेक्सिको-कनाडा समझौता

• SALIENT PROVISIONS(प्रमुख प्रावधान):

• Environmental Protection (पर्यावरण संरक्षण)

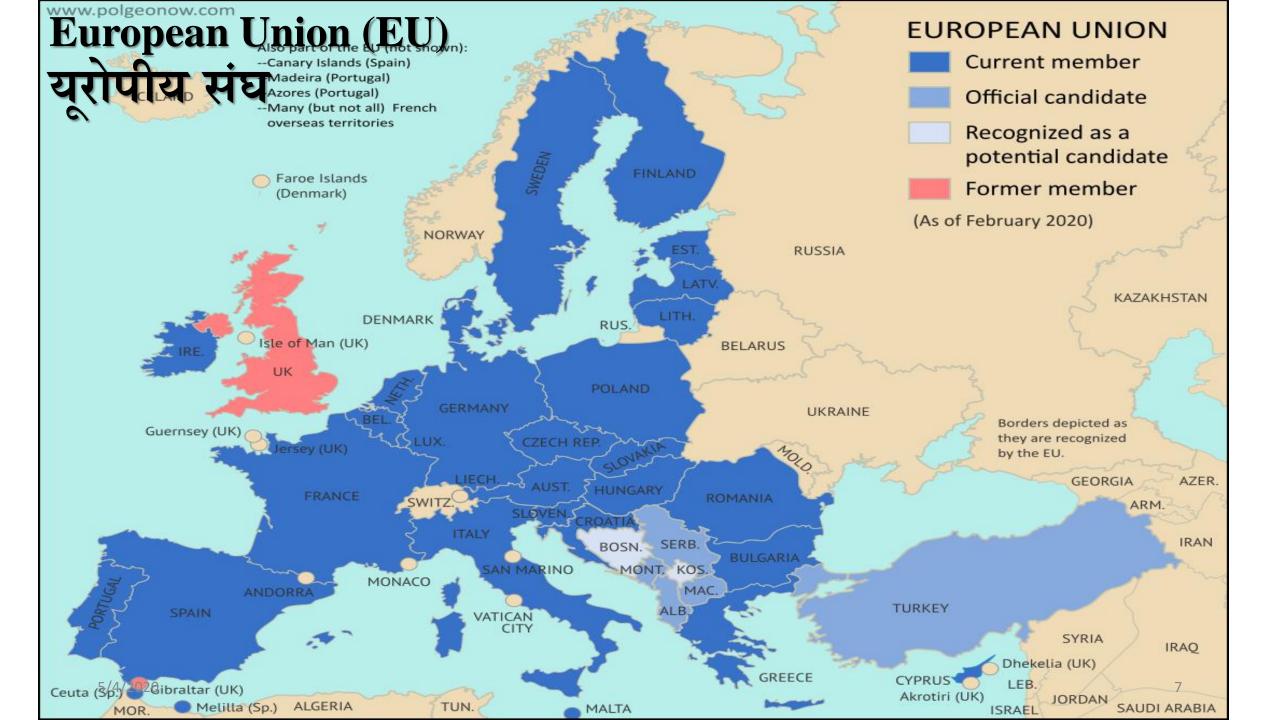
• USMCA provides for increased protection of whales, fishes and other marine wildlife from pollution, illegal fishing and overfishing.

(यूएसएमसीए व्हेल, मछलियों और अन्य समुद्री वन्यजीवों के प्रदूषण से बचाव के लिए अधिक सुरक्षा प्रदान करता है खासकर अवैध मछली पकड़ने और ओवरिफिशिंग से।)

• Review after 6 years (बौद्धिक संपदा अधिकार)

USMCA stipulates that the member nations will review the agreement after 6 years. If all the member nations agree, then the deal will continue for the full 16-years period with necessary changes if any.

यूएसएमसीए यह निर्धारित करता है कि सदस्य राष्ट्र 6 साल के बाद समझौते की समीक्षा करेंगे। यदि सभी सदस्य देश सहमत होते हैं, तो पूरे 16 साल की अवधि के लिए आवश्यक परिवर्तन के साथ यह सौदा जारी रहेगा।



European Union (EU) यूरोपीय संघ

- Establishment Date: November 1, 1993
- Type of Economic Grouping: Economic and Political Union
- Member Nations: Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czechia, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden (27 Members)
- United Kingdom withdrew from the European Union on 31st January, 2020 through the Brexit process. UK is the first country to leave EU.
- (यूनाइटेड किंगडम 31 जनवरी, 2020 को ब्रेक्सिट प्रक्रिया के माध्यम से यूरोपीय संघ से खुद बाहर हो गया। यूरोपीय संघ छोड़ने वाला वह पहला देश है।)
- After two World Wars the European countries realised that it is better to work together than fight against each other. (दो विश्व युद्धों के बाद यूरोपीय देशों ने महसूस किया कि एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई की तुलना में एक साथ काम करना बेहतर है।)

European Union (EU) यूरोपीय संघ

- In recent years European Union has emerged as a developed economic grouping. Most of the member nations have adopted Euro as their shared common currency. (हाल के वर्षों में यूरोपीय संघ एक विकसित आर्थिक समूह के रूप में उभरा है। अधिकांश सदस्य देशों ने यूरो को अपनी साझा आम मुद्रा के रूप में अपनाया है।)
- European Union facilitates free movement of people, goods, services and money (capital) from one nation of the European Union to another. For this purpose the European Union made the 'Schengen Area', which is an area without borders. Thus persons can travel from country to country freely without going through checks and controls while crossing national borders. (यूरोपीय संघ लोगों, वस्तुओं, सेवाओं और धन (पूंजी) के यूरोपीय संघ के एक देश से दूसरे देश में मुक्त आवागमन की सुविधा देता है। इस उद्देश्य के लिए यूरोपीय संघ ने 'शेंगेन क्षेत्र' बनाया, जो बिना सीमाओं वाला क्षेत्र है। इस प्रकार व्यक्ति राष्ट्रीय सीमाओं को पार करते हुए चेक और नियंत्रणों के बिना एक देश से दूसरे देश स्वतंत्र रूप से यात्रा कर सकते हैं।)

European Union (EU) यूरोपीय संघ

• Member countries are encouraged to enact similar or uniform legislations in socioeconomic justice and home affairs and maintain common policies on trade, agriculture, fisheries, environmental protection and regional development.

(सदस्य देशों को सामाजिक-आर्थिक न्याय और गृह मामलों में समान कानून बनाने और व्यापार, कृषि, मत्स्य पालन, पर्यावरण संरक्षण और क्षेत्रीय विकास पर आम नीतियों को बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।)

• Recently, the corona-virus pandemic (January- April, 2020) has to some extent eroded the belief of the people in the cohesive European Union. The member countries appeared to be fighting their lone battle against the spread of highly contagious Covid-19 virus instead of having a cooperative approach to dealing with the problem and the concept of the 'Schengen Area' remains suspended during the crisis.

(हाल ही में, कोरोना-वायरस महामारी (जनवरी- अप्रैल, 2020) ने यूरोपीय संघ की एकजुटता में लोगों के विश्वास को कुछ हद तक कम कर दिया है। सदस्य देश समस्या से निपटने के लिए एक सहयोगी दृष्टिकोण रखने के बजाय, अत्यधिक संक्रामक कोविद -19 वायरस के प्रसार के खिलाफ अपनी लड़ाई अलग-थलग लड़ते दिखाई दिए और इस संकट के दौरान 'शेंगेन क्षेत्र' की अवधारणा निलंबित रही।)

Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ (आसियान)



• Establishment Date: 8 August 1967

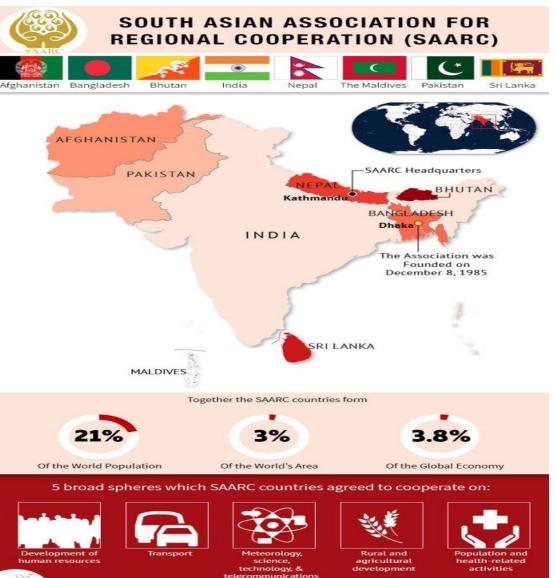
• Member Nations: Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand and Vietnam (10 Members)

Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ (आसियान)

- AIMS & PURPOSES:
- The aims and purposes of ASEAN as per ASEAN Declaration are:
- To accelerate the economic growth, social progress and cultural development in the region through joint endeavours in the spirit of equality and partnership in order to strengthen the foundation for a prosperous and peaceful community of Southeast Asian Nations;
- To promote regional peace and stability through abiding respect for justice and the rule of law in the relationship among countries of the region and adherence to the principles of the United Nations Charter;
- To promote active collaboration and mutual assistance on matters of common interest in the economic, social, cultural, technical, scientific and administrative fields;
- To provide assistance to each other in the form of training and research facilities in the educational, professional, technical and administrative spheres;
- To collaborate more effectively for the greater utilisation of their agriculture and industries, the expansion of their trade, including the study of the problems of international commodity trade, the improvement of their transportation and communications facilities and the raising of the living standards of their peoples;
- To promote Southeast Asian studies; and
- To maintain close and beneficial cooperation with existing international and regional organisations with similar aims and purposes, and explore all avenues for even closer cooperation among themselves.

Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ (आसियान)

- आसियान घोषणा के अनुसार आसियान के उद्देश्य हैं:
- दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के एक समृद्ध और शांतिपूर्ण समुदाय के लिए नींव को मजबूत करने के लिए समानता और साझेदारी की भावना में संयुक्त प्रयासों के माध्यम से क्षेत्र में आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास में तेजी लाना ;
- न्याय के लिए सम्मान और क्षेत्र के देशों के बीच संबंधों में कानून के शासन और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों का पालन करने के माध्यम से क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को बढ़ावा देना;
- आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी, वैज्ञानिक और प्रशासनिक क्षेत्रों में सामान्य हित के मामलों पर सक्रिय सहयोग और पारस्परिक सहायता को बढ़ावा देना;
- शैक्षिक, व्यावसायिक, तकनीकी और प्रशासनिक क्षेत्रों में प्रशिक्षण और अनुसंधान सुविधाओं के रूप में एक दूसरे को सहायता प्रदान करना;
- उनके कृषि और उद्योगों के अधिक उपयोग के लिए और अधिक प्रभावी ढंग से सहयोग करने के लिए, उनके व्यापार का विस्तार, अंतर्राष्ट्रीय वस्तु व्यापार की समस्याओं का अध्ययन, उनके परिवहन और संचार सुविधाओं में सुधार और उनके लोगों के जीवन स्तर को बढ़ाना;
- दक्षिण पूर्व एशियाई अध्ययन को बढ़ावा देना ; तथा
- समान उद्देश्य और उद्देश्यों के साथ मौजूदा अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों के साथ घनिष्ठ और लाभप्रद सहयोग बनाए रखने के लिए, और आपस में भी निकट सहयोग के लिए सभी रास्ते तलाशना।



© 2018 MapsofWorld.com

- Establishment Date: 8 December 1985
- Member Nations: Afghanistan, Bangladesh,

Bhutan, India, Maldives,

Nepal, Pakistan and Sri Lanka.

(8 Members)

Contribution of Various #SAARC NATIONS towards COVID-19 EMERGENCY RELIEF FUND:

- AFGHANISTAN: 1 Million \$
- ▶ NEPAL: 1 Million \$
- BANGLADESH: 1.5 Million \$
- ■BHUTAN: 100,000 \$
- MALDIVES: 200,000 \$
- SRI LANKA: 5 Million \$
- INDIA: 10 Million \$

#SAARCfightsCorona

- Objectives of SAARC as per its Charter :
- To promote the welfare of the peoples of South Asia and to improve their quality of life;
- To accelerate economic growth, social progress and cultural development in the region and to provide all individuals the opportunity to live in dignity and to realize their full potentials;
- To promote and strengthen collective self-reliance among the countries of South Asia;
- To contribute to mutual trust, understanding and appreciation of one another's problems;
- To promote active collaboration and mutual assistance in the economic, social, cultural, technical and scientific fields;
- To strengthen cooperation with other developing countries;
- To strengthen cooperation among themselves in international forums on matters of common interests; and
- To cooperate with international and regional organizations with similar aims and purposes.

15

- दक्षेस के उद्देश्य:
- दक्षिण एशिया के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने और उनके जीवन स्तर में सुधार लाना ;
- क्षेत्र में आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास में तेजी लाने के लिए और सभी व्यक्तियों को गरिमा में रहने और अपनी क्षमता का एहसास करने का अवसर प्रदान करना;
- दक्षिण एशिया के देशों के बीच सामूहिक आत्मिनर्भरता को बढ़ावा देना और मजबूत करना;
- एक दूसरे की समस्याओं के आपसी विश्वास, समझ और प्रशंसा में योगदान करना;
- आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्रों में सिक्रिय सहयोग और पारस्परिक सहायता को बढ़ावा देना;
- अन्य विकासशील देशों के साथ सहयोग को मजबूत करना;
- सामान्य हितों के मामलों पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों में आपस में सहयोग को मजबूत करना; तथा
- समान लक्ष्य और उद्देश्यों वाले अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों के साथ सहयोग करना।

• At various forums of SAARC, unanimous decisions are attempted. Bilateral and contentious issues are out of the purview of the Association.

दक्षेस के विभिन्न मंचों पर, सर्वसम्मित से निर्णय लेने का प्रयास किया जाता है। द्विपक्षीय और विवादास्पद मुद्दे संघ के दायरे से बाहर होते हैं।

• The 19th summit of SAARC was supposed to be held in Islamabad on 15-16 November 2016. India including Afghanistan, Bhutan, Bangladesh, Sri Lanka and Maldives did not attend SAARC SUMMIT due to 2016 Uri attack. Pakistan postponed the SAARC summit and announced that new dates would be released soon, but it did not happen.

दक्षेस का 19वां शिखर सम्मेलन 15-16 नवंबर 2016 को इस्लामाबाद में होना था। उड़ी हमले के कारण भारत, अफगानिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव सम्मेलन में शामिल नहीं हुए। पाकिस्तान ने सार्क सम्मेलन स्थिगत कर दिया और घोषणा की कि नई तारीखें जल्द ही जारी की जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

• Because of bad bilateral relation between Indian and Pakistan, SAARC has failed to achieve its objectives in various areas of cooperation.

भारत और पाकिस्तान के बीच खराब द्विपक्षीय संबंध के कारण, दक्षेस सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों में अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में विफल रहा है।

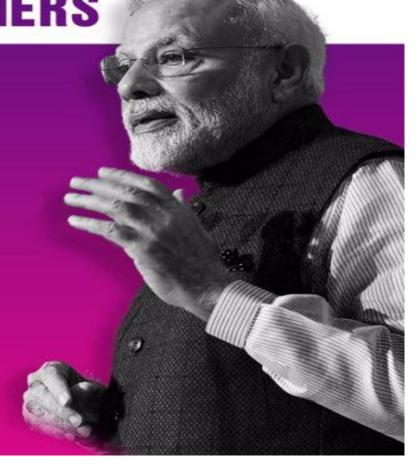
• On March 15, 2020 Indian Prime Minister Shri Narendra Modi took leadership initiative during the ongoing corona-virus pandemic and convened a video conference of the SAARC nations' representatives and urged all to cooperate in dealing with the threat of Covid-19 disease. India pledged US\$10 million towards Covid-19 Emergency Fund. Thereafter other member nations also contributed towards the fund for collective welfare all the member nations.

15 मार्च, 2020 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने चल रहे कोरोना-वायरस महामारी के दौरान नेतृत्व की पहल की और सार्क देशों के प्रतिनिधियों का एक वीडियो सम्मेलन बुलाया और कोविद -19 बीमारी के खतरे से निपटने में सभी से सहयोग करने का आग्रह किया। भारत ने कोविद -19 आपातकाल राहत कोष के लिए US \$ 10 मिलियन देने का वादा किया। तत्पश्चात अन्य सदस्य राष्ट्रों ने भी सभी सदस्य राष्ट्रों के सामूहिक कल्याण के लिए कोष में योगदान दिया।

#SAARCfightsCorona

INDIA'S OFFER TO SAARC PARTNERS

- Creation of a COVID-19 Fund with voluntary contributions from all Members; India's initial pledge of US \$10 million
- Indian Rapid Response Teams, of doctors, specialists and testing equipment.
- Online training capsules for emergency response staff using the model India used to raise capacity of emergency staff across India.
- A review video conference of doctors and medical professionals, to consider specific measures and best practices.
- A review video conference of trade officials to consider the impact of travel restrictions on intra-regional trade.

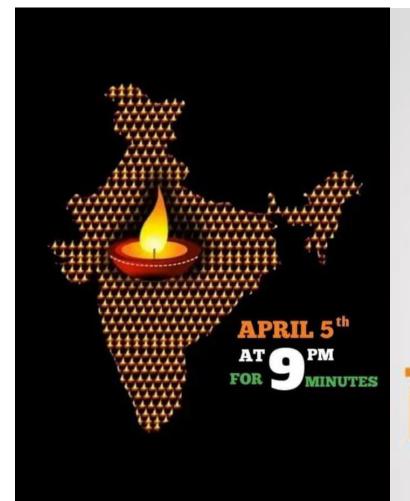


#SAARCfightsCorona

INDIA'S OFFER TO SAARC PARTNERS

- Help prepare a website with informational material in all SAARC languages.
- Sharing software in our own Integrated Health Information Platform for Disease Surveillance, and training to use this MIS system.
- Use of the SAARC Disaster Management Centre, to identify and popularize best practices in fighting Covid-19.
- Proposal for creating a Research Platform for all SAARC States to share ideas and proposals for diagnostic and therapeutic interventions for diseases and epidemics.
- Evolve common SAARC Pandemic Protocols to be applied on all borders.







आ नो भद्रा: क्रतवो यन्तु विश्वत: | Let noble thoughts come to us from every side.